



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 284]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 जून 2017—आषाढ़ 2, शक 1939

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जून 2017

क्र. एफ 7-19-2014-उन्तीस-1.—चूंकि, राज्य सरकार की यह राय है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में, जहां उचित मूल्य की दुकानें नहीं हैं पात्र परिवारों की सुविधा की दृष्टि से एक उचित मूल्य दुकान खोला जाना आवश्यक है;

अतएव, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय (नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता विभाग) के एस. ओ. 681 (ई) तथा 682 (ई) दोनों दिनांक 30 नवम्बर, 1974 और कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) के जी. एस. आर. 800, दिनांक 9 जून, 1978 के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

#### संशोधन

उक्त आदेश में,—

1. कण्डिका 9 में,

(1) उप-कण्डिका (1) में, शब्द “ग्रामीण क्षेत्र और” का लोप किया जाए.

(2) उप-कण्डिका (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-कण्डिकाएं अन्तःस्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

“(1-क) जिले के प्रत्येक जनपद पंचायतों की ऐसी ग्राम पंचायतें, जहां वर्तमान में उचित मूल्य दुकानें स्थापित नहीं हैं, उनकी कुल संख्या की यथासंभव एक तिहाई दुकानें महिला संस्थाओं को आवंटित की जाएगी. ऐसी उचित मूल्य की दुकान की विक्रेता भी महिला ही होगी.

(1-ख) यदि उन ग्राम पंचायतों में, जहां उचित मूल्य की दुकान उपलब्ध नहीं है, पात्र महिला संस्था द्वारा कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो ऐसी दुकानें अन्य पात्र संस्थाओं को आवंटित की जा सकेंगी.

(1-ग) ग्रामीण क्षेत्र की पात्र संस्थाओं द्वारा वर्तमान में संचालित दुकानें इस नियंत्रण आदेश में भविष्य में अन्यथा उपबंधित होने तक यथावत चलती रहेंगी.

No. F-7-19-2014-XXIX-1.—WHEREAS, the State Government is of the opinion that in the interest of eligible households it is expedient and necessary to open fair price shops in every such Panchayat where there is no fair price shop;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 3, read with Section 5 of Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and in persuasion of S. O. 681 (E) and S. O. 682 (E) both dated 30th November, 1974 of Ministry of Industries and Civil Supplies (Department of Civil Supplies and Cooperation) and GSR 800, dated 9th June, 1978 of Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Public Distribution System (Control) Order, 2015, namely :—

#### AMENDMENTS

In the said Order,—

1. In clause 9,—

(1) In sub-clause (1), the words “area and in rural” shall be omitted.

(2) After sub-clause (1), the following sub-clauses shall be inserted, namely :—

“(1-a) As far as possible in every Janpad Panchayat, one third of total number of such Village Panchayats having no fair price shops, shall be allotted fair price shops to women institution. The salesperson in such Fair Price shops shall also be woman.

(1-b) if no application is submitted by the women institution for allotment of Fair Price Shops in those village Panchayat where no Fair Price Shop is available, then such shops shall be allotted to other eligible institution.

(1-c) The existing Fair Price Shops operated by eligible institutions / societies shall be continued until otherwise provided in this control order in future.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. के. चन्देल, उपसचिव.